MIRZA INTERNATIONAL LIMITED





December 27, 2017

To, **BSE Limited**Floor 25, P. J. Towers
Dalal Street,
Mumbai – 400 051

National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex Bandra (East), Mumbai-400 001

Dear Sirs.

Sub: Submission of newspaper advertisement as per Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Pursuant to the Provisions of Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith the copies of the newspaper advertisements published in both the English and Hindi edition of Business Standard regarding the publication of completion of dispatch of Postal Ballot Notice and Postal Ballot Form on December 26, 2017

Kindly acknowledge the receipt.

Thanking You

Yours faithfully

For MIRZA INTERNATIONAL LIMITED

(Ankit Mishra) Company Seretary

Enclosure: as above

सक्षेप में

विशेषज्ञों ने दी जीएसटी स्लैब घटाने की सलाह

वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) को लागृ हुए छह माह पूरे होने को हैं लेकिन कारोबारी अभी इसके साथ पूरी तरह सहज नहीं हो पाए हैं। ऐसे में विशेषज्ञों ने सरकार और कारोबारियों के बीच तालमेल व सहयोग बढाने और कर स्लैब की संख्या घटाने की सलाह दी है। कारोबारियों का कहना है कि जीएसटी के स्लैब पांच से घटाकर तीन किए जाने चाहिए तथा सेवाओं पर कर की दर बढाने के नकारात्मक प्रभाव पर भी गौर करने की जरूरत है। विशेषज्ञों के अनुसार सरकार हालांकि, उद्यमियों की जीएसटी से जुड़ी तमाम परेशानियों को दूर करने के लिए हरसंभव कदम उठा रही है, लेकिन जीएसटी के वास्तविक व्यवहार में आने वाली समस्याओं को जल्द से जल्द दूर किए जाने

निर्माण, इंजीनियरिंग ऑटो क्षेत्र में नई भर्तियां

निर्माण, इंजीनियरिंग और ऑटो क्षेत्र में नौकरियों की भर्ती में तेजी से नवंबर महीने में पिछले साल के मुकाबले कुल भर्तियों में 16 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। साथ ही यह आने वाले महीनों में नौकरियों में तेजी का रुख रहने का संकेत दे रहा है। रोजगार संबंधी सलाह देने वाली वेबसाइट नौकरी डॉट कॉम का जॉब स्पीक सूचकांक इस साल नवंबर में 2,113 पर रहा। यह नौकरी बाजार में सुधार का संकेत देता है। नौकरी डॉट कॉम के मुख्य बिक्री अधिकारी वी सरेश ने कहा, जॉब स्पीक सचकांक में नवंबर में सालाना आधार पर 16 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई।

स्टेशनों के विकास की नई नीति

नई दिल्ली. 26 दिसंबर

•रत के रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए रेल मंत्रालय 1 लाख करोड़ रुपये की लागत से स्टेशनों के पुनर्विकास की योजना पेश करने की तैयारी में है। योजना की मंजरी के लिए मंत्रालय जनवरी में कैबिनेट के समक्ष प्रस्ताव पेश करेगा। प्रस्तावित योजना में डेवलपरों के पट्टे की अवधि बढ़ाकर 99 साल कर दिया गया है। इससे भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम (आईआरएसडीसी) और रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) को और ज्यादा वित्तीय स्वतंत्रता के साथ स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए बाजार से धन जुटाने के अधिकार मिलेंगे।

इस मामले से जुड़े एक सूत्र ने कहा, 'अंतरमंत्रालय सलाह के लिए रेल मंत्रालय एक कैबिनेट नोट जारी करने जा रहा है, जिस पर वित्त और कानन मंत्रालय की राय ली जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि इस नीति को जनवरी के दूसरे पखवाडे में कैबिनेट की मंजूरी मिल जाएगी।' इसके पहले 23 स्टेशनों के विकास के लिए निविदा जारी की गई थी, जिस पर उद्योग जगत की बहुत सुस्त प्रतिक्रिया मिली। इसे देखते हुए सरकार ने स्टेशनों के पुनर्विकास योजना में बदला करने का फैसला



कररहे हैं। इस कदम का मकसद

निवेशकों का विश्वास बहाल करना

है। रेलवे की सहायक इकाइयां जैसे

आईआरएसडीसी और आरएलडीए

अगर हर परियोजना में 20-30

प्रतिशत निवेश करेंगी तो नया

निवेशक इनसे जुड़ सकता है।'

पहले चरण में 15 स्टेशनों को लिया

जा सकता है, जिनके पुनर्विकास

पर 6,000 से 7,000 करोड़ रुपये

डेवलपर भी आकर्षित हो सकते हैं

क्योंकि डेवलपर अब रेल परिसर

में पुनर्विकास वाले क्षेत्र की 20

प्रतिशत जमीन का इस्तेमाल

आवासीय मकसद से कर सकते हैं।

शेष 80 प्रतिशत जगह का इस्तेमाल

वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए होगा।

बहरहाल नई नीति संभवत:

इस नीति से रियल एस्टेट

निवेश होगा।

इसके अलावा उद्योग जगत के दिग्गजों जैसे टाटा समूह, शपूरजी पलोनजी, जीएमआर, एस्सेल समह और एलऐंडटी ने नीति की शर्तों की लेकर रेल मंत्री पीयूष गोयल के समक्ष अक्टूबर महीने में चिंता जताई थी। नई नीति के मुताबिक आईआरएसडीसी स्टेशनों के पनर्विकास के लिए नोडल एजेंसी होगी। कंपनी बाजार से धन जुटा सकती है और स्टेशनों के पुनर्विकास, के लिए इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण पर उसे खर्च कर सकेगी। परियोजना के लिए सभी मंजरियां मिलने के बाद कंपनी वाणिज्यिक विकास के लिए निजी कंपनियों को आमंत्रित करेगी।रेलवे के मुताबिक नई नीति से निवेशकों के लिए जोखिम कम होगा।

उन्होंने कहा, 'हम इसके लिए

ज्यादा स्वायत्तता

- नई नीति के तहत 400 स्टेशनों का होना है पुनर्विकास
- पहले चरण में 15 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा सकता है
- कुल परियोजना १ लाख करोड़ रुपये की, जनवरी में मिल सकती है कैबिनेट की मंजूरी
- इसके पहले की नीति निजी क्षेत्र

को नहीं कर सकी थी आकर्षित 4,00 संभावित स्टेशनों पर विचार

हबीबगंज, कोझिकोड और जम्मू जैसे स्टेशनों पर लागू नहीं होगी जिनका ठेका पहले ही दिया जा चका है। पहले की नीति के मृताबिक निजी कंपनियों को स्विस चैलेंज मोड पर डिजाइन पेश करनी थी, जबिक अब रेलवे आर्किटेक्ट की नियुक्ति कर सकता है, जो कुछ मानक डिजाइन देगा।

आईआरएसडीसी को ज्यादा वित्तीय स्वायत्तता देने की कवायद के तहत इसे इरकॉन और रेलवे भिम विकास प्राधिकरण का समान संयुक्त उद्यम इस साल की शुरुआत में बनाया गया था। इसके पहले यह इरकॉन की सहायक इकाई थी। आईआरएसडीसी की 25 सितंबर को हुई सालना बैठक में इरकॉन की 1 प्रतिशत हिस्सेदारी 40 लाख रुपये में आरएलडीए को देने को मंजूरी दी गई थी।

2018 में ब्रिटेन-फ्रांस को पीछे छोड़ सकता है भारत

लंदन, 26 दिसंबर

भारत अगले साल ब्रिटेन व फ्रांस को पीछे छोड़ते हुए डॉलर के हिसाब से विश्व की पांचर्वी सबसे बडी अर्थव्यवस्था वाला देश बन सकता है। सेंटर फॉर इकोनॉमिक ऐंड बिजनेस रिसर्च (सीईबीआर) कंसल्टेंसी की 2018 के लिए वर्ल्ड इकर्नॉमिक लीग की तालिका में वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेजी रहने का अनुमान लगाया गया है, जिसे सस्ती ऊर्जा व तकनीक से बल मिलेगा।

भारत के अग्रणी देश बनने का अनुमान उस धारणा का हिस्सा है, जिसके तहत अगले 15 साल तक प्रमुख 10 बडी अर्थव्यवस्थाओं में एशिया की अर्थव्यवस्थाओं का दबदबा रहने का अनुमान लगाया गया है।

सीईबीआर के डिप्टी चेयरमैन डगलस मैकविलियम्स ने कहा, 'अस्थायी झटकों के बावजूद भी भारत की अर्थव्यवस्था फ्रांस व ब्रिटेन को 2018 में पीछे छोड देगी और डॉलर के हिसाब से दुनिया की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी।

मैकविलियम्स ने कहा कि भारत की वृद्धि दर नोटबंदी और नए बिक्री कर की वजह से सुस्त हुई है। यह रॉयटर्स की ओर से अर्थशास्त्रियों के बीच कराए गए सर्वे से सामने आया है।

सीईबीआर ने कहा है कि चीन 2032 तक विश्व की सबसे बडी अमेरिका की अर्थव्यवस्था को पीछे छोडकर पहले पायदान पर पहुंच सकता है।

रिपोर्ट में कहा गया है. 'कारोबार पर

कारोबारी भरोसा नीचे

भारत में कारोबारी लोगों का रुख व्यापक तौर पर सकारात्मक बना हुआ है। हालांकि उनके भरोसे का स्तर चार साल के निचले स्तर पर आ गया है जबकि इसी अवधि में एशिया प्रशांत क्षेत्र में यह पिछले दो साल के उच्च स्तर पर है। ग्रांट थॉर्नटन की एशिया प्रशांत: व्यापार और संपन्नता रिपोर्ट के अनुसार एशिया-प्रशांत व्यापार भरोसे का स्तर दो साल के उच्च स्तर पर है। इसकी प्रमुख वजह चीन और जापान जैसी दो बडी अर्थव्यवस्थाओं का प्रदर्शन बेहतर होना है।

राष्ट्रपति ट्रंप का असर अनुमान की तुलना में कम गंभीर रहा है। ऐसे में अमेरिका वैश्विक अगुआई फिलहाल कायम रखेगा।'

ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था अगले 2 साल में फ्रांस से पीछे छूट जाएगी वहीं सीईबीआर का अनुमान है कि जितना डर था, उसकी तुलना में ब्रिटेन पर ब्रेक्जिट का असर कम रहेगा, जिसकी वजह से 2020 में ही फ्रांस की अर्थव्यवस्था के आगे निकलने की संभावना है।

कच्चे तेल की कीमतें कम होने की वजह से रूस की स्थिति में उतार चढ़ाव की संभावना बनी हुई है और यह माना जा रहा है कि 2032 तक रूस बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में 17वें स्थान पर पहुंच सकता है, जबकि अभी 11वें स्थान पर है।

बढ़ेंगे अनुबंध के कर्मचारी

निश्चित या सीमित अवधि के लिए रखे गए कर्मचारी को भी उसी कारखाने में काम करने वाले स्थायी कर्मचारियों को मिलने वाली सभी सुविधाएं दी जाती हैं। इन सुविधाओं में काम के समान घंटे, समान वेतन और भत्ते शामिल हैं। हालांकि यह

आवश्यक नहीं है कि नियोक्ता ठेके पर रखे गए इन कर्मचारियों को निकालने से पहले नोटिस दे। साथ ही नियोक्ता बिचौलियों से बात किए बगैर कर्मचारी को सीधे ठेके पर भी रख सकता है।

परिधान क्षेत्र में निश्चित अवधि के लिए काम पर रखने की सुविधा प्रदान करते समय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने अपने बयान में कहा था. 'यह कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के लिए फायदेमंद है क्योंकि नियोक्ता को बाजार की मांग के हिसाब से कर्मचारी रखने का मौका मिल जाता है और यह भी सुनिश्चित होता है कि ठेके पर रखे गए कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों जैसे ही लाभ और कामकाजी स्थितियां मिलें।'

किसी निश्चित अवधि में ही होने वाले काम से संबंधित कंपनियां आम तौर पर परियोजना से संबंधित नौकरियों पर स्थायी कर्मचारी रखने से परहेज करती हैं। इसकी वजह यह है कि उन्हें हटाने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत छंटनी के नियमों का पालन

करना पड़ता है। इसके तहत नोटिस देना पड़ता है, मुआजवा देना पड़ता है और सरकार को भी पहले से बताना होता है।

राजग सरकार ने अप्रैल 2015 में ठेके पर रोजगार देने के संबंध में दिशानिर्देश का मसौदा जारी किया था, लेकिन कर्मचारी संघों के विरोध के बाद यह प्रस्ताव ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। 2003 में राजग सरकार ने सीमित अवधि के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति की छूट दी थी, लेकिन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) ने यह प्रावधान समाप्त कर दिया था।

होटल के कमरे का किराया । लाख रुपये के पार

अजय मोदी

नई दिल्ली, 26 दिसंबर

यह नए कर की कहानी है। नए साल के मौके पर छुट्टियां बिताने वाले प्रमुख स्थलों जैसे गोवा में होटलों की मांग बढ़ने से कमरे के किराये में चार गुना बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) भी कुछ होटलों पर सामान्य जीएसटी दरों की तुलना में

ताज एग्जॉटिका रिसॉर्ट ऐंड स्पा का ही मामला लें। मेक माई ट्रिप इसके गार्डन व्य वाले विला का एक रात का किराया 80,700 रुपये दिखा रहा है, जिसमें ब्रेकफास्ट भी शामिल है। लेकिन यह केवल होटल का किराया है। आपको 28 प्रतिशत के हिसाब से 22,800 रुपये जीएसटी का भी भुगतान करना होगा। इससे इसमें एक रात ठहरने का कुल किराया 1,04,320 रुपये हो जाता है। अगर आप इसी होटल में 31 जनवरी की रात को ठहरने के लिए कमरा लेते हैं तो किराया 20.700 रुपये है और जीएसटी के साथ कुल खर्च 26,720 रुपये आता है। नए साल के मौके पर होटल का जितना किराया लिया जा रहा है, उतने किराये में दो लोग बाली और मॉरिशस जैसे लोकप्रिय अंतरराष्ट्रीय

पर्यटक स्थलों पर 5-6 रात ठहर सकता हैं. जिसमें ठहरने के साथ उड़ान, स्थानीय परिवहन का भी किराया शामिल होगा।

शहर में ताज की एक और प्रॉपर्टी ताज फोर्ट अदुआडा रिसॉर्ट ऐंड स्पा का एक सुपीरियर गार्डन व्यू रूम का ब्रेकफास्ट के साथ एक रात का किराया 52,000 रुपये है। 14,800 रुपये जीएसटी के साथ एक रात ठहरने का कुल किराया 67,840 रुपये है। अगर आप इसी कमरे को 31 जनवरी की रात के लिए बुक करते हैं तो किराया 13,200 रुपये होगा और जीएसटी के साथ एक रात का किराया 17,120 रुपये है।

शहर की एक और लग्जरी प्रॉपर्टी द लीला का जीएसटी के पहले एक कमरे का किराया ब्रेकफास्ट के साथ 55,989 रुपये था और अब 15,677 रुपये जीएसटी के साथ लागत 71,642 रुपये है। इसी होटल का 31 जनवरी को किराया 21,196 रुपये होगा और जीएसटी के बाद 27,321 रुपये किराया लगेगा। अन्य लोकप्रिय पर्टलन स्थलों

जैसे उदयपुर में ताज लेक पैलेस के सभी कमरे इस साल के अंतिम दिन के लिए भर चुके हैं। झील के बीच में बने इस होटल में 66 कमरे

जीएसटी की मार

ा नए साल पर मेक माई ट्रिप में गोवा के ताज एग्जॉटिका रिसॉर्ट ऐंड स्पा के एक रात का किराया 1,04,320 रुपये पहुंचा

 गोवा, कॉर्बेट, रणथंभीर, माउंट आबू और पचमढ़ी जैसे कुछ जाने माने पर्यटन स्थलों पर होटलों का किराया 13 से 30 प्रतिशत तक बढ़ा

और 17 स्वीट हैं। 87 कमरों वाले होटल ओबेरॉय उदयविलास में भी सभी कमरे बक हैं। एक अन्य होटल ट्राइडेंट के 137 कमरों और 4 स्वीट में से एक भी खाली नहीं इस साल का दिसंबर पिछले

साल की तुलना में अलग है। नोटबंदी की वजह से पिछले साल होटल और ट्रैवल उद्योग पर जबरदस्त मार पडी थी और क्रिसमस और नया साल मंद रहा। गोवा, उदयपुर, जयपुर और मनाली में होटल पहले ही भर चुके हैं। इस बार होटल का किराया थोड़ा डायनॉमिक है और कमरों की संख्या में कमी के साथ किराये में बढोतरी हुई है। ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल बिग ब्रेक्स के प्रबंध निदेशक कपिल

गोस्वामी ने कहा, 'हवाईजहाज के किराये की तरह होटल के किराये भी गतिशील रहे हैं और हम देख रहे हैं कि मांग के आधार पर रोजाना किराया बदल रहा है। पिछले साल की तुलना में इस साल मांग में कम से कम 20 प्रतिशत की बढोतरी नजर आ रही है क्योंकि पिछले साल नोटबंदी का असर था, लोग अपने वित्तीय प्रबंधन में लगे हए थे।'

क्रिसमस और नए साल के मौके पर भारत के लोग घरेल पर्यटन केंद्रों को ज्यादा पसंद करते हैं। होटल की खोज और किराये तक होटलों के किराये मे की तुलना करने के लिए बने पोर्टल ऑफसीजन की तुलना में 50 ट्रिवागों के मुताबिक भारतीय लोग प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है और जिन 10 प्रमुख पर्यटन केंद्रों पर जाना पसंद करते हैं, उनमें दुबई मांग वाले दिनों में किराये में 30 से और सिंगापुर को छोड़कर बाकी 40 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हुई है।

भारतीय केंद्र हैं। गोवा पहले स्थान पर है और अन्य 10 प्रमुख पर्यटन स्थलों में जयपुर, पुरी, उदयपुर और मनाली शामिल हैं। सस्ते होटल मुहैया कराने वाली

ओयो का कहना है कि इस साल गोवा, कॉर्बेट, रणथंभौर, माउंट आब और पचमढ़ी जैसे कुछ पर्यटन स्थलों पर होटलों का किराया सालाना आधार पर 13 से 30 प्रतिशत तक बढा है। ऑनलाइन ट्रैवल फर्म यात्रा के अध्यक्ष शरत ढल ने कहा कि दिसंबर के आखिर क्रिसमस और नए साल जैसे ज्यादा

सार्वजनिक परिवहन पर सरकार का ध्यान

पृष्ठ 1 का शेष...

मंत्रालय 25,000 करोड़ रुपये के प्रस्तावित इलेक्ट्रिक बसों और पीआरटी पहल को भी अपने समर्थन को विस्तार देने को इच्छुक है, जिसमें से 2,000 करोड़ रुपये इलेक्टिक बसों को खरीदने के लिए होंगे। यह बसें मौजूदा डीजल बसों का स्थान लेंगी और इतना ही धन पोड टैक्सी जैसे व्यक्तिगत द्रुतगामी परिवहन के प्रोत्साहन के लिए होगा। सरकार जल्द ही देश की पहली चालक रहित पोड टैक्सी व्यवस्था शरू करने के लिए रुचि

पत्र (ईओआई) आमंत्रित करेगी, जिसे दिल्ली के धौला कुआं से हरियाणा के मानेसर के बीच चलाया जाना है।

केंद्र सराकर ने बस पोर्ट के विकास की भी परिकल्पना की है, जो राज्य सरकारों के साथ मिल कर बडे शहरों में बनाए जाएंगे। इस योजना के व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) के लिए 2,000 करोड़ रुपये अलग से रखे जाएंगे।

सडक मंत्रालय ने लंदन की परिवहन व्यवस्था की तर्ज पर राज्य परिवहन अंडरटेकिंग के परिचालन

मॉडल की भी परिकल्पना की है। ग्रेटर लंदन, इंगलैंड में परिवहन व्यवस्था का दायित्व स्थानीय निकाय पर होता है।

योजना के तहत एसटीय बसों के बेडे की खरीद के लिए पुंजी नहीं लगाएगी बल्कि इसकी जगह कंपनियों से टेंडर आमंत्रित करेगी और प्रति किलोमीटर किराये के भुगतान के आधार पर बसें चलाने के लिए हिस्सेदार बनाया जाएगा। इन बसों के किराये का निर्धारण राज्य सरकार करेगी, जिसे केंद्र सरकार का समर्थन होगा।



MIRZA INTERNATIONAL LIMITED

CIN: L19129UP1979PLC004821

Registered Office.: 14/6, Civil Lines, Kanpur - 208001 website: www.mirza.co.in; e-mail: ankit.mishra@redtapeindia.com Tel.: +91 512 2530775; Fax: +91 512 2530166

NOTICE FOR VOTING THROUGH POSTAL BALLOT

embers are hereby informed that the dispatch of the Postal Ballot Notice dated 7th November, 2017 (along with th Explanatory Statement and Postal Ballot Form) to the members of the Company in respect of the passing of the resolution for the matter stated therein, by way of Postal Ballot, which includes voting by electronic means has been completed or 26th December, 2017. The said documents were sent in electronic mode to those members who have registered their e-mail address with the Company or with the depositories and physical mode to the other members.

The aforesaid Resolution is to be transacted by means of Postal Ballot and Electronic Voting (e-voting) in terms of Section 110 of the Companies Act. 2013 ("the Act") read with the Rules 22 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014. Karvy Computershare Pvt. Ltd. ("Karvy") has been engaged by the Board of Directors of the Company for providing the

Members, whose name are recorded in the Register of Members of the Company or Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the closure of the record date i.e. 08/12/2017, will be entitled to cast their vote either by Postal Ballo or e-voting. A person who is not member on the record date should accordingly treat the Postal Ballot Notice for informatior purpose only. Member(s), who have not received postal ballot forms may write to the Company and obtain a duplicate thereof Voting through Postal Ballot will commence at 9.00 a.m. on Monday, 1st January, 2018 and end at 5.00 p.m. on Tuesday 30th January, 2018. Postal Ballot Form received after 5.00 p.m. on Tuesday, 30th January, 2018 will be considered invalid. The period for e-voting starts at 9.00 a.m. on Monday, 1st January, 2018 and ends at 5.00 p.m. on Tuesday, 30th January 2018, e-voting will be blocked by Karvy at 5.00 p.m. on Tuesday, 30th January, 2018.

Voting by Postal Ballot or e-voting shall not be allowed beyond the said date and time. Mr. K.N. Shridhar, Practicing Compan Secretary (Membership No.:3882), has been appointed as Scrutinizer for conducting the Postal Ballot and e-voting process ir

In case of any grievances/queries connected with the voting by Postal Ballot including voting by electronic means, members may contact Mr. Ankit Mishra, Company Secretary at 14/6, Civil Lines, Kanpur-208001 or to the RTA of the Company at Karvy Computershare Private Limited, Karvy Selenium Tower B, Plot number 31 & 32, Gachibowli, Financial District Nanakaramguda, Hyderabad 500 032.

The result of the voting through postal ballot process shall be declared on 31st January, 2018. The Postal Ballot Notice is available on the Company's Website www.mirza.co.in and on the website of Karvy Computershare Private Limited (Karvy) ww.evoting.karvy.com For Mirza International Limited

Date: 26.12.2017 Place: Kanpur



Ankit Mishra Company Secretary ACS 30650

बीएस सूडोकू 3007 परिणाम संख्या 3006



8 6 1 2 4 7 9 7 5 3 6 8 2 1 8 4 6 2 9 1 4 9 5 2 6 8 7 3 2 8 6 7 9 3 4 8 1 2 6 5 9 7 3 9 4 2 1 7 5 8 6 6 5 7 3 4 8 9 1 2 कैसे खेलें?

मुश्किल

उत्तर प्रदेश

आईएमपीसीएल में पूरी हिस्सेदारी बेचेगी सरकार

नई दिल्ली, 26 दिसंबर

सरकार ने इंडियन मेडिसिंस फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईएमपीसीएल) में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर ली है और ऐसी फर्म की तलाश में है जो कंपनी की संपत्ति का मूल्यांकन कर सके। आईएमपीसीएल आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं का विनिर्माण और उनकी आपूर्ति करती है और यह आयुष मंत्रालय के अंतर्गत सरकार के नियंत्रण में है। इसमें 98.11 प्रतिशत हिस्सेदारी भारत सरकार की है, जबकि शेष 1.89 प्रतिशत हिस्सेदारी उत्तराखंड सरकार की पीएसयू की है।

आवेदन प्रस्ताव (आरएफपी) आमंत्रित करते हुए सरकार ने कहा है, 'भारत सरकार आईएमपीसीएल में दो स्तर की नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से आईएमपीसीएल में अपनी 100 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने पर विचार कर रही है। आयष मंत्रालय को इसके लिए प्रतिष्ठित संपत्ति मूल्यांकनकर्ता की जरूरत है, जो इसके मूल्यांकन का काम कर सके।'

बोलीकर्ता मंत्रालय में 15 जनवरी तक अपनी बोली दाखिल कर सकते हैं।

क्षेत्रीय मंडियों के भाव

बंद भाव रुपये प्रति क्विंटल दिल्ली

अनाज : गेहूं म.प्र. (देसी) २०८०-२२८०, गेहूं दड़ा (मिल के लिए) 1770-1785, चक्की आटा (डिलिवरी) 1780-1785, आटा राजधानी (१० किग्रा) २६०-३००, शक्तिभोग (१० किग्रा) २५५-२९०, रोलर फ्लोर मिल ९६०-९७०, (५० किग्रा), मैदा 990-1000 (50 किग्रा), सूजी 1050-१०६० (५० किग्रा), परमल कच्चा २३००-2350, परमल वैन्ड 2350-2400, सेला २७७०-२९००, चावल आई आर आठ १९२५-१९७५, बाजरा १२१५-१२२०, ज्वार पीला १३७५-१४२५, सफेद २७५०-२८५०, मक्का 1285-1290, जौ 1470-1480, दलहन : उडद ४०५०-५६५०, उडद छिलका (स्थानीय) ५१००-५२००, उड़द बेहतरीन 5200-5700, धोया 5600-5800, मूंग

4900-5600, दाल मुंग छिलका स्थानीय

५७००-५९००, मूंग धोया स्थानीय ६३००-

6800, बेहतरीन गुणवत्ता 6800-7000,

मसूर छोटी 3750-3900, बोल्ड 3850-4000, दाल मसूर स्थानीय 3900-4400, बेहतरीन गुणवत्ता ४०००-४५००, मलका स्थानीय ४४००-४६००, मलका बेहतरीन गुणवत्ता ४५००-४८००, मोठ ३६००-४०००, अरहर ४३५०, बेसन (३५ किग्रा) शक्तिभोग २२५०, राजधानी २२५०, राजमा चित्रा ६०००-८३००, काबुली चना छोटी 7800-8800,

गेहूं लूज 1535/1540, जो 1500/1510, चावल मसूरी 2200/2250, चावल मोटा 2100/2140, सरसों 3550/3625, तिल सफेद ८५००/८६००, सोया (टीन) 1130/1170, तेल सरसों कच्ची वैट पेड (टीन) १३२०/ १३५०, सरसों खल 1800/1850, पामोलिन 1100/1110, वनस्पति घी (यूपी एफओआर) 1170/1180, अलसी 4400/4450,

अनाज एवं दाल-दलहनः गेहूं दड़ा

चावल शरबती सेला ३४००/३४५०, स्टीम 5200/5300, लालमती 3100/3200, चावल (सोना) 2600/2700,

१६३०/१६४०, गेहुं शरबती २१७७/२२२५,

हर रो, कॉलम और 3

बाई 3 के बॉक्स में

तक की संख्या भरें।

एक से लेकर नौ

(प्रति किलो): मैन्था ऑयल १८००, बोल्ड क्रिस्टल (१२ नं.) २१००, फ्लैक १९१०, डीएमओ १२५५, टरपीन लैस बोल्ड २२०० मुजफ्फरनगर

गुड़ (40 किलो): चाकू 1030/1100, खरपा १०००/१०५०, लङ्डू ११००/११५०, रसकट ९००/९२०, शक्कर ११५०/१२००, चीनी मिल डिली. (क्विं.) (जीएसटी अतिरिक्त)ः खतौली ३५२२, देवबंद 3310, सिहोरा 3300, बुंदकी 3320, धामपुर ×, चीनी हाजिर 3700/3750

गुड़-चीनीः चीनी हाजिर 3700/3750, गुड़ (प्रति ४० किलो) बाल्टी 1000/1020, तिलहनः सरसों (४२ प्रतिशत कंडी.) ३९००, खलः सरसों २०५०/२१००, बिनौला 2150/2250, चना छिलका १९००/२०००, चोकर मोटा (३४ किलो)

जयपुर

राजस्थान

अनाजः चावल डीबी 6300/6400, गेहूं (मिल) 1680/1700. मक्की १३००/१३१०, बाजरा ११५०/११६०, जौ १४६०, ग्वार लूज ३८००/३८५०, ज्वार कैटलफीड १३००/१३५०, ज्वार बेस्ट क्वालिटी 1900/2000, तेल-तिलहनः सरसों(मिल पहुंच) ४१२५, सरसों एक्सपेलर निवाई ७८५०, कोल्हू कच्ची घानी टोंक ८०००, राइसब्रान डिऑयल्ड

कंटीन्यूअस×, डीओसी (टन)ः सरसों

जयपुर १४७०, कोटा १४४००, अलवर

14200, निवाई × श्रीगंगानगर

गेहूं (ढेरी) 1700/1750, ग्वार (ढेरी) 3825/3850, जो 1450/1460, सरसों लूज 3600/3650, बिनौला खल 2000/2025

गेहूं 1750/1760, जौ 1425/1450,

पोपकोन मझी 3800/4000, ग्वार डिलीवरी (ऑलपेड)४१००/४१५०,

जीएसटी अतिरिक्त (प्रति क्वि)ः राइसब्रान (खाद्य)(प्रति प्वाइंट)८७७. राइसब्रान (अखाद्य) ८६, खल सरसों 1780, डीओसीः राइसब्रान बैच सफेद 660, लाल 650, कंटीन्यूअस 700, सरसों (टन) १४८००, सूरजमुखी (टन) १३०००, अनाजः गेहूं १७६०/१७७०, आटा (५० किलो) ९९०, मैदा १०६०, चोकर (४९ किग्रा) ८६५, चोकर (३० किग्रा) ५२०, फाजिल्का

गेहूं 1625/1630, सरसों 3625/3675, ਣਵੇਂ (प्रति मन): (जे-34) 4175/4200, कपास देशी ४२५०/४३००, कपास नरमा (क्विं.) 5200/5300, बिनौला (टैक्सपेड): खल 2200/2250, जे-34 (चिलकी)

भाषा/एनएनएस 2425/2460

Pidilite's shares fell two per cent after its buyback programme size of ₹500 crore and price of ₹1,000 apiece disappointed investors. The Street was expecting more, given that the stock had gained 10 per cent to record highs last week

OUICK TAKE: PIDILITE'S BUYBACK DISAPPOINTS

TSI P13 INDIGO, **SPICEJET GET** WINGSTO **FLY HIGHER**

COMMODITIES P16 FRUIT & VEGETABLE EXPORTS FALL ON STRINGENT GLOBAL **QUALITY NORMS**

Market sees flurry of QIPs in Dec

10 companies, highest in 7 years, follow this route to raise funds this month



DEEPAK KORGAONKAR & PUNEET WADHWA Mumbai/New Delhi, 26 December

here is a rush to tap funds through the qualified institutional placement (QIP) route, with 10 companies, including banks, having launched QIP issues in December so far — highest in the past seven years in terms of number of issues.

Total eight companies, including Punjab National Bank, Mahindra & Mahindra Financial Services, Natco to ₹24,000 crore to fund growth by selling shares to

Pharma and Union Bank of India, have raised ₹11,037 crore via QIPs this month. Most of these intend to use the proceeds primarily to repay or prepay outstanding indebtedness and towards capital expenditure. The financials proposed to use funds to augment their long-term resources for meeting capital requirements and to augment their capital adequacy ratios.

In April 2010, total 10 companies had raised ₹2,723 crore, while in September 2009 (₹6,245 crore) and in December 2008 (₹9,412 crore) 10 firms had mobilised more than ₹6,000 crore through QIPs. In value terms, during June 2017, three companies had raised ₹17.505 crore via this route, the PRIME Database data shows

Kridhan Infra and Srikalahasthi Pipes have opened their QIP issues on Wednesday, December 20. These two companies proposed to raise ₹400 crore, taking the total tally by 10 QIPs to ₹11,437

crore. Of these 10 firms, eight have mobilised ₹9,667 crore in the past two weeks alone. "After a very long time, buoyancy in markets has sustained. Investors, both domestic and foreign, have redeployed funds in the equity market. Till the markets remain vibrant, people/promoters will like to collect money for future growth, and this trend is likely to continue in 2018 as well. We can expect this to change only if there is a change in market conditions," said A K Prabhakar, head of

MONEY MATTERS

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

* Till December 26

Source: Prime Database/BSE

QIP issues

Number ₹ crore

41 23,339

53 34,676

59 26,147

9 3,459

12 4,705

10 8,075

33 31,684

32 19,065

16 4,712

41 56,800

3,935

3,586

16

QIPs, after two muted years, have shown signs of revival, with capital raised via 41 QIPs reaching a new high of ₹56,800 crore (12 times higher than in 2016) so far in 2017. This number has surpassed the previous year's ₹4,712 crore, and is the highest till date, beating the earlier peak of ₹34,676 crore raised by 53 companies in 2009.

In the banking space, HDFC Bank, the country's second-biggest lender by assets, had said it would raise up

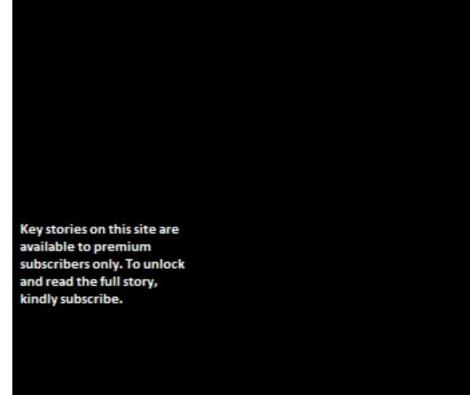
investors, including a preferential issue to its parent Housing **Development Finance Corporation** (HDFC). Canara Bank, too, is reportedly considering raising funds via

"As regards HDFC Bank, I think it is creating a war chest for the next five years. Promoters want to make the most of the market conditions right now." Prabhakar said.

And, the investors who subscribed to these issues have been rewarded well in some cases. Given the market conditions, stocks of 28 of the 40 companies that raised funds via this route are trading above their QIP price. Minda Industries (up 208 per cent), Deepak Nitrite (122 per cent) and Delta Corp (101 per cent) have seen their market price more than double compared with their QIP prices. Ramkrishna Forgings and Camlin Fine Sciences

have rallied 65 per cent and 51 per cent, respectively. "The trend of raising money via QIPs is likely to continue. From a period where people were doing a lot of off-market transactions to give private equity players an exit route, we are now talking about growth capital. This underlying trend is likely to continue. Public sector banks took this route as they wanted to position themselves before the recapitalisation by the government," said Munish Aggarwal, director (capital markets), Equirus Capital.

THE COMPASS RCom's asset sale at lower valuations



Sebi may ease **FPI norms**

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, 26 December

The Securities and Exchange Board of India (Sebi) is mulling easing access norms for investment by foreign portfolio investors (FPIs) and bringing a new framework to strengthen the governance structure for mutual funds (MFs), senior officials have said.

Also, Sebi has plans to review the framework for credit rating agencies (CRA), as it seeks to check the menace of 'rating shopping' and 'pick-and-choose' approach in governance model for MFs

ties to achieve the minimum public shareholding requirements. These issues would be taken up at the Sebi board schedule for

Thursday, senior officials said. With regard to FPIs, the markets watchdog may consider simplifying regulatory requirements pertaining to access norms, with a view to easing direct registration for

overseas investors. The regulator will review the norms for CRA on the basis of public comments. It had come out with a consultation paper in this regard in 1. Sebi may create a full-time September. According to the proposal, no CRA should "directly or indirectly hold more than 10 per cent of shareholding and/ or voting rights in another CRA and shall not have representation on the board of the other CRA".

The minimum net worth institutional placement.



The regulator also moots new

Further, the regulator is threshold for the rating agentional method for listed enti- raised to ₹50 crore from the current level of ₹5 crore. In addition. Sebi is considering to revisit its directive on 'loan default disclosure', which will make it mandatory for listed companies to inform stock exchanges about such issues as soon as they occur.

Earlier, Sebi had put off implementation of its directive "until further notice" that required listed firms to inform exchanges if they default on loan payments to banks and financial institutions, just a day before it was supposed to be implemented on October post of Chief Vigilance Officer. Further, it plans to make amendments to Investment Advisor norms on the basis of consultation paper that was issued in June this year. Also, it is looking to amend regulation with respect to qualified

661 STOCKS DOUBLE IN 2017; 🛬
661 STOCKS DOUBLE IN 2017; > 2.7 TIMES MORE THAN LAST YEAR
More than 600 stocks have doubled this

year, 2.7 times more than last year. However, the tally is much less than the peak of previous Bull Run in 2007 when over 1,000 stocks had doubled. It is even less than the number in 2009 (1,158 stocks doubled) – when the market saw a sharp v-shaped recovery following the 2008 Global Financial Crisis. This year the market has seen broad-based gains, supported by both global and domestic liquidity. The mid- and smallcap indices have delivered superior returns than the benchmark Sensex. Last year, the market was relatively flat. This year's rally after demonetisation lows in end-December has been a oneway street, with barely any sharp corrections. The low volatility has helped spur risk appetite of investors. Of the 600 multi-baggers, over 150 stocks have gained three times or more. The biggest gainers of 2017 are little-known companies. Shree Ganesh Biotech and Ashari Agencies have seen their share price gain 20 times. Among the notable names in the big multi-baggers are graphite makers HEG, Graphite India and Goa Carbon; broking firm Indiabulls Ventures and poultry company Venky's Compiled by Samie Modak

	No. of	Change (%)					
Calendar	multi-		BSE	BSE			
year	baggers*	Sensex	Midcap	Smallcap			
2007	1,029	47	69	74			
2008	22	-52	-67	-69			
2009	1,158	81	108	115			
2010	333	17	16	17			
2011	64	-25	-34	-36			
2012	308	26	39	36			
2013	158	9	-6	-10			
2014	935	30	55	63			
2015	433	-5	7	6			
2016	246	2	8	2			

TOP 10 GAINERS OF 2017 Gain (No. of times) 19.0 Shree Ashari California Indiabulls RSD Mauria

Udyog

Software

*Stocks gaining 100% or more; Note: Universe is all BSE listed companies

Ventures

Top MF holdings see little change in 2017

Agencies

Ganesh

HDFC Bank, ICICI Bank remain biggest bets; Tata Motors, HCL Tech, Sun Pharma ousted from top 15

CHANDAN KISHORE KANT Mumbai, 26 December

Mutual fund managers played safe in 2017 when it came to their top holdings. In a year that saw several scheme categories deliver market-beating moved up one notch to fourth 30 per cent-plus returns, the list of companies most owned by mutual funds remained the same, by and large

There were only five stocks at the start of the year in which mutual fund exposure was over ₹10,000 crore. At the end 10. Fund managers tried to remain with trusted businesses in the large-cap category and kept on pumping inflows into select counters.

State Bank of India (SBI), Infosys and Larsen & Toubro (L&T) were the five mostowned stocks. Infosys slipped two notches to fifth spot with SBI replacing it and L&T

available in the core part of the Development portfolio. At best, we can juggle holdings but we cannot do away with any. Infosys, despite facing tremendous difficulties, has no alternative," said the of the year, this number rose to chief investment officer of a large fund house.

> churning, however, lower November, nearly a fourth of down the order. Tata Motors, total equity assets and up from HCL Technologies and Sun ₹1.32 lakh crore a year ago.

HDFC Bank, ICICI Bank, Pharmaceuticals, which were among the top 15 most-owned stocks at the beginning of the vear, were replaced by GAIL.

NTPC and Bharti Airtel. Maruti Suzuki, the sixth most-owned stock at the beginning of the year, has slipped three notches down "There are very few choices to ninth spot. Housing Finance Corporation (HDFC) jumped from 13th spot to sixth. ITC and Reliance Industries continued to retain their previous spots.

In all, mutual funds equity assets in the top 15 stocks stood There was significant at ₹2.12 lakh crore by

TOP 15 STOCKS OWNED BY MFs THEN AND NOW

Finance

Holdings

Consumer

Sources: BSE, Complied by BS Research Bureau

101 13 STOCKS OWNED BY THIS THEN AND NOW							
De	cember 2016	Nov	November 2017				
Stocks	Exposure (₹ crore)	Stocks	Exposure (₹ crore)				
HDFC Bank	22,651	HDFC Bank	35,178				
ICICI Bank	14,080	ICICI Bank	23,936				
Infosys	13,197	Infosys	15,577				
State Bank of India	12,018	State Bank of India	18,874				
Larsen & Toubro	10,288	Larsen & Toubro	18,317				
Maruti Suzuki	7,936	Maruti Suzuki	11,595				
ITC	6,869	ITC	12,829				
Reliance Industries	6,598	Reliance Industries	11,631				
IndusInd Bank	6,554	IndusInd Bank	9,232				
Axis Bank	5,965	Axis Bank	9,097				
Sun Pharmaceuticals	5,839	Kotak Mahindra Bank	10,866				
Kotak Mahindra Bank	5,711	Bharti Airtel	7,318				
HDFC	5,220	HDFC	13,042				
HCLTechnologies	5,025	NTPC	7,307				
Tata Motors	4,659	GAIL India	7,226				
Total	1,32,610		2,12,025				

Note: Open-ended equity funds have only been considered

Source: Value Research

Petronet is well placed for more gains

Key stories on this site are available to premium subscribers only. To unlock kindly subscribe.



Date: 26.12.2017

Place: Kanpur

MIRZA INTERNATIONAL LIMITED

CIN: L19129UP1979PLC004821

Registered Office.: 14/6, Civil Lines, Kanpur - 208001 website: www.mirza.co.in; e-mail: ankit.mishra@redtapeindia.com Tel.: +91 512 2530775; Fax: +91 512 2530166

NOTICE FOR VOTING THROUGH POSTAL BALLOT

Members are hereby informed that the dispatch of the Postal Ballot Notice dated 7th November, 2017 (along with the Explanatory Statement and Postal Ballot Form) to the members of the Company in respect of the passing of the resolution for the matter stated therein, by way of Postal Ballot, which includes voting by electronic means has been completed on 26th December, 2017. The said documents were sent in electronic mode to those members who have registered their e-mail address with the Company or with the depositories and physical mode to the other members.

 $The aforesaid \, Resolution \, is \, to \, be \, transacted \, by \, means \, of \, \, Postal \, Ballot \, and \, Electronic \, Voting \, (e-voting) \, in \, terms \, of \, Section \, 110 \, decreases \, (e-voting) \, for the electronic \, Voting \, (e-voting) \,$ of the Companies Act. 2013 ("the Act") read with the Rules 22 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014. Karvy Computershare Pvt. Ltd. ("Karvy") has been engaged by the Board of Directors of the Company for providing the

Members, whose name are recorded in the Register of Members of the Company or Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the closure of the record date i.e. 08/12/2017, will be entitled to cast their vote either by Postal Ballot or e-voting. A person who is not member on the record date should accordingly treat the Postal Ballot Notice for information purpose only. Member(s), who have not received postal ballot forms may write to the Company and obtain a duplicate thereof. Voting through Postal Ballot will commence at 9.00 a.m. on Monday. 1st January, 2018 and end at 5.00 p.m. on Tuesday, 30th January, 2018. Postal Ballot Form received after 5.00 p.m. on Tuesday, 30th January, 2018 will be considered invalid. The period for e-voting starts at 9.00 a.m. on Monday, 1st January, 2018 and ends at 5.00 p.m. on Tuesday, 30th January,

2018, e-voting will be blocked by Karvy at 5.00 p.m. on Tuesday, 30th January, 2018. Voting by Postal Ballot or e-voting shall not be allowed beyond the said date and time. Mr. K.N. Shridhar, Practicing Company Secretary (Membership No.:3882), has been appointed as Scrutinizer for conducting the Postal Ballot and e-voting process in

In case of any grievances/queries connected with the voting by Postal Ballot including voting by electronic means, members may contact Mr. Ankit Mishra, Company Secretary at 14/6, Civil Lines, Kanpur-208001 or to the RTA of the Company at Karvy Computershare Private Limited, Karvy Selenium Tower B, Plot number 31 & 32, Gachibowli, Financial District Nanakaramguda, Hyderabad 500 032.

The result of the voting through postal ballot process shall be declared on 31st January, 2018. The Postal Ballot Notice is available on the Company's Website www.mirza.co.in and on the website of Karvy Computershare Private Limited (Karvy For Mirza International Limited

Ankit Mishra REDTAPE Company Secretary ACS 30650